

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी
30प्र0 शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
30प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जवाहर भवन लखनऊ।

न्याय अनुभाग-7 (क0नि0)

लखनऊ

दिनांक 27 दिसम्बर, 2017

विषय - लोक अदालत में कार्यरत आशुलिपिक के पद अनुमन्य ग्रेड वेतन रू02400/- का वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय दिनांक 08-09-2010 व शा0दे0 दिनांक 27-02-2013 के अनुसार ग्रेड वेतन रू02800/- किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1116/एसएलएसए-21/2011 दिनांक 19 मई 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 30प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रथम चरण में गठित 23 लोक अदालतों में कार्यरत आशुलिपिकों को वर्तमान में वेतन बेंड-1 रू0-5200-20200 तथा ग्रेड वेतन रू02400/- प्रदान किया जा रहा है। सम्यक् विचारोपरान्त 30प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ प्रथम चरण में 23 जनपदों में गठित स्थायी लोक अदालतों में कार्यरत आशुलिपिकों के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रू02400/- को वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय विषयक शासनादेश संख्या- वे0आ0'-2-2056/दस-54(एम)/2008टी0सी0 दिनांक 08-09-2010 व शा0दे0स0-वे0आ0-2-109/दस-54 (एम)2008टीसी दिनांक 27-02-2013 के अनुसार तात्कालिक प्रभाव से ग्रेड वेतन रू0 2800/- अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- ग्रेड वेतन में वृद्धि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-1385/दस-2017 दिनांक 15 दिसम्बर 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

उमेश कुमार
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, 30प्र0(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, इलाहाबाद।
- 2- मा0 कार्यपालक अध्यक्ष , 30प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ ।
- 3- संबंधित जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
- 4 - संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- वित्त (व्यय नियन्त्रण)अनुभाग-12/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
- 7- न्याय अनुभाग-09 (बजट)
- 8- गार्ड फ़ावली।

आज्ञा से,

राजेश पति त्रिपाठी

विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।